यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/118/2017 **दिनांक :** 29.12.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वेतन पुनरीक्षण पर वार्ता में देरी पर यूएफबीयू द्वारा सरकार को पत्र

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/37/2017/37 दिनांक 29.12.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

वेतन पुनरीक्षण – समझौता वार्ता में देरी – यूएफबीयू का सरकार को पत्र लिखना

हालांकि, आईबीए तथा यूएफबीयू के बीच समझौता वार्ता मई, 2017 में आरंभ हो गई, अभी तक, बैठकों के कई दौर के बावजूद जिसमें गैर–वित्तीय माँगों पर चर्चा हुई है, आईबीए हमारी वित्तीय माँगों पर चर्चा करने के लिए आगे नहीं आई है। इसलिए यूएफबीयू ने 28.11.2017 को आईबीए को बैठक आयोजित करने और वेतन पुनरीक्षण माँग पर अपना प्रस्ताव करने का उनसे आग्रह करते हुए पत्र लिखा।

हालांकि, आईबीए की ओर से कोई जबाव नहीं मिला और इसलिए यूएफबीयू ने अब सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को मामले में उनके हस्तक्षेप की माँग करने के लिए पत्र लिखा है।

यदि मामले में और देरी होती है, तो हमें वेतन पुनरीक्षण में शीघ्रता के लिए आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों पर निर्णय लेना होगा।

इस बीच, हम अपनी इकाईओं और सदस्यों की जानकारी के लिए सरकार को यूएफबीयू के पत्र का प्रलेख नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को यूएफबीयू का पत्र दिनांक 28.12.2017

विषय : बैंकिंग क्षेत्र में वेतन पुनरीक्षण

आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि 10वें द्विपक्षीय समझौते और अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण की अवधि 31.10.2017 को समाप्त हो गई और इसलिए वेतन और सेवा शर्तों का पुनरीक्षण 01.11.2017 से बैंकिंग क्षेत्र में देय है।

चूंकि पूर्व में समझौते पर पहुंचने में हमेशा पर्याप्त देरी हुई है और इसे टालने के लिए, अति शीघ्र अर्थात् 12.01.2016 को बैंकों और इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को पत्र जारी करते हुए सरकार (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय) द्वारा एक सक्रिय पहल की गई थी जिसमें उन्हें वार्तालाप की प्रक्रिया शुरू करने और 01.11.2017 से पहले इसे अन्तिम रूप से तय करने की सलाह दी गई थी।

इस पत्र का 24.8.2016, 1.10.2016, 21.12.2016, 21.3.2017, 22.8.2017 और 13.12.2017 को बैंकों/ आईबीए को सरकार द्वारा स्मरण कराया गया।

सरकार के पत्र को ध्यान में रखते हुए, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स को आमंत्रित किया और 02.5.2017 को वार्ता शुरू की। यह आश्वासन दिया गया था कि 01.11.2017 से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए सम्पूर्ण वार्ता शीघ्रता से की जाएगी।

तब से पिछले सात महीनों में कई बैठकें आयोजित की गईं और विभिन्न गैर–वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभी तक इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन वेतन पुनरीक्षण के लिए हमारी माँग पर किसी प्रस्ताव के साथ आगे नहीं आई है। अपने प्रस्ताव को पेश करने के आईबीए को हमारे बार–बार अनुरोध के बावजूद जिस पर आगे की वार्ता की जा सकती है, आईबीए उस पर शमसान की शान्ति अपनाये हुए है।

आईबीए की नेगोशिएटिंग कमेटी की आखिरी बैठक 27.10.2017 को हुई थी जब हमें आश्वस्त किया गया था कि आईबीए जल्द ही बैठक आयोजित करेगी और अपना प्रस्ताव पेश करेगी लेकिन हमने अभी तक उनसे कुछ भी नहीं सुना है। जाहिर है, यह हमारे सदस्यों के बीच उत्कंठा और बेचैनी पैदा कर रहा है।

यह अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है कि आईबीए को बिना किसी देरी के वार्तालाप आयोजित करने और वेतन पुनरीक्षण की मात्रा पर चर्चा शुरू करने की सलाह दी जाए जिससे कि जल्द से जल्द समझौते को अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जा सकें।